

'नई शिक्षा नीति में उभरते राष्ट्र की आकांक्षाएं'

सीआरएसयू में बहु-विषयक शिक्षा पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन, राज्यपाल रहे मुख्यातिथि

जागरण संवाददाता जीद : चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार बहु-विषयक शिक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला हुई। जिसमें सुबह उद्घाटन शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने किया और शाम को समापन अवसर पर राज्यपाल असीम कुमार घोष मुख्यातिथि रहे।

कार्यशाला में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के बीसी भी पहुंचे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा राज्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में प्रगति व विकास का पयाय बन रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक उभरते हुए राष्ट्र की आकांक्षाएं शामिल हैं। जिसमें युवा अपनी बुद्धि के बलबूते पर 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार रहेगा। तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परितृश्य में, जहां विज्ञान और मानविकी, प्रौद्योगिकी और कला, अनुसंधान और उद्यमिता के बीच की सीमाएं लगातार कमजोर होती जा रही हैं। यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली समग्र विचारकों, नवप्रवर्तकों और समस्या-समाधान कर्ताओं का पोषण करेगी।

विषयों का यह सम्मिश्रण आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और हमारे छात्रों को अनिश्चित दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक अनुकूलनशीलता विकसित करने में



कार्यशाला में मंच पर बैठे राज्यपाल असीम कुमार घोष, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिश्रा • सो. चित

हुड्डा, सैलजा, रणदीप गुप की लिस्ट बनकर रह गई

शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष की लिस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि यह हुड्डा, सैलजा, रणदीप गुप की लिस्ट बनकर रह गई है। केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोपों पर महिपाल ढांडा ने कहा कि वोट चोरी तो चोरी करे और ऊपर से सीनाजोरी करने, बाली बात हो गई। उल्टा वोट चोरी तो उन्होंने ही की थी, तभी तो 50 से 90 सीट जीत गए। हमारी सरकार तो वोट चोरी पर अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। वोटर लिस्ट को रिवाइज करवा रहे हैं, इसमें उनको परेशानी क्यों हो रही है। प्रदेश में विपक्ष नेता न होने पर ढांडा ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस विपक्ष का नेता नहीं बना पा रही है। जबकि सत्ता पक्ष के साथ-साथ मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी होता है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि अध्यापकों की आनलाइन ट्रांसफर जल्द शुरू होगी।

सक्षम बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की सोच के अनुरूप 2047 तक विकसित भारत का विजन, एक समृद्ध, समावेशी, विश्व स्तर पर सम्मानित भारत, इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज जनमानस का कितने प्रभावी ढंग से पोषण करते हैं, शिक्षा ही इस यात्रा की आधारशिला है। शिक्षा में लचीला पाठ्यक्रम छात्रों को अपनी गति और तरीके से सीखने की अनुमति देता है। इस महत्वाकांक्षी

एजेंडे की सफलता केवल नीतिगत घोषणाओं पर ही नहीं, बल्कि उसे साकार करने के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता शिक्षकों, प्रशासकों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और समाज पर निर्भर करेगी। हमें शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल बुनियादी ढांचे, अनुसंधान तंत्र के साथ-साथ अपने शिक्षार्थियों में नैतिकता, सहानुभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों को स्थापित करना चाहिए। राष्ट्रीय



सीआरएसयू में कार्यशाला में उपस्थित प्रदेशभर की विवि के बीसी व शिक्षाविद्।

नई शिक्षा नीति कैम्पस में वास्तविक रूप में पहुंचे : शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए बीसी और शिक्षाविद् को संबोधित करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैम्पस में वास्तविक रूप से पहुंचे और वर्तमान पीढ़ी में सम्मिलित हो। भारत के शिक्षा के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। ज्ञान के साथ-साथ कौशल विकास जरूरी है। हमें विद्यार्थियों को एक संकय में सीमित नहीं रखकर अलग-अलग विषयों व शोध का ज्ञान देना होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। सरकार सभी के सुझावों को लेकर कार्य करेगी।

शिक्षा नीति के आदर्शों को क्रियान्वित करके वर्ष 2047 तक जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, उस समय भारत न केवल एक ज्ञान महाशक्ति होगा, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र भी होगा जो शिक्षा का उपयोग करके सच्ची समता, समावेशिता और सतत विकास प्राप्त कर रहा होगा।

बीसी प्रोफेसर रामपाल सैनी ने मुख्यातिथि राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और शिक्षा मंत्री महिपाल

ढांडा को स्मृति चिह्न भेंट किया।

इस अवसर पर राज्यपाल की धर्मपत्नी मित्रा घोष, डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिश्रा, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा के चेयरपर्सन कैलाश चंद्र शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू, सीआरएसयू के बीसी प्रोफेसर रामपाल सैनी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर लवलीन मोहन सहित अन्य विश्वविद्यालयों के बीसी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से होंगे नए आयाम स्थापित : राज्यपाल

जींद (जुलाना), 18 अगस्त (हप्र)

राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में नए आयाम स्थापित होंगे। नई शिक्षा नीति एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेगी। हरियाणा ने इसे लागू कर लिया है और इसके सभी आयामों के लक्ष्य को निश्चित तौर पर हासिल करेगा। उच्च शिक्षा में पहुँच, गुणवत्ता, समानता, स्थिरता और भविष्य की तैयारी वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिन पर राज्य सरकार का दृष्टिकोण आधारित है। सेमिनार में आयोजित सत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित, बहु-विषयक शिक्षा के विविध पहलुओं पर उच्च गुणवत्तापूर्ण चर्चा हुई। हमारी नई शिक्षा नीति केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो 2025 के अंत तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अधिकांश भाग को लागू करने जा रहा है। यह वास्तव में एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति

2020 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद को बधाई दी।

राज्यपाल असीम कुमार घोष सोमवार को चौधरी रणबीर सिंह विवि (सीआरएसयू) जींद में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार बहु-विषयक शिक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिट्टा व सीआरएसयू के वीसी ने स्मृति चिन्ह भेंट कर राज्यपाल का स्वागत किया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सरकार द्वारा मॉडल स्कूल, स्किल हब और बहु-प्रवेश/निकास प्रणाली को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों को लचीला और आधुनिक शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

इस अवसर पर राज्यपाल की पत्नी मित्रा घोष, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा के चेयरपर्सन कैलाश चन्द्र शर्मा आदि प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य : महीपाल

जौद, 18 अगस्त (ललित) : हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। प्रदेश में जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर शिक्षा दी जा रही है वहीं उन्हें शिक्षित करने के साथ-साथ हुनरमंद करने की योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं ताकि हमारे बच्चों में कौशल हो और वे अपने हुनर की बदौलत अपने पैरों पर खड़े होकर प्रदेश एवं देश का नाम रोशन कर सकें। किसानों की सुविधा के लिए किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे जिससे उन्हें कृषिकार्यों में मदद मिल सकेगी। सरकार के एजेंडे में किसान हित सर्वोपरि है।

वह सोमवार को गांव संगतपुरा की सामान्य चौपाल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने गांव में ई-लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि



संगतपुरा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा।

अगर तय मापदंड होते हैं तो सरकारी स्कूल को पी.एम. श्री स्कूल का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके साथ-साथ उन्होंने ग्रामीणों की सामुदायिक भवन की मांग पर कहा कि इसकी फिजीबिलिटी चैक करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, बेटों के साथ-साथ बेटियों को भी बराबर का दर्जा देकर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए। हम सभी को अपने

बुजुर्गों का पूरा मान-सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभव का लाभ लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक सभ्य समाज की स्थापना में अपना योगदान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों के हितों में जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के बनाए गए हैं जिसमें आर्थिक रूप से सहायता दी जा रही है। किसानों की समृद्धि के लिए अनेकों योजनाएं निरंतर लागू की जा रही हैं।

प्रदेश में किसानों की फसल एम.एस.पी. पर खरीद कर उनकी फसल का भुगतान समयबद्ध सीधा खातों में डाला जा रहा है। किसानों की बदौलत ही देश के भंडार भरे हुए हैं।

वर्तमान परिवेश में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनानी चाहिए, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। किसानों का सम्मान रखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 6 हजार रुपए वार्षिक की सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। वर्तमान सरकार ऐसी पहली सरकार है जो जनता के सुझाव लेकर काम करती है।

शिक्षा मंत्री को ग्रामीण ट्रेक्टर-ट्राली के माध्यम से पुष्पवर्षा करते हुए सभा स्थल तक लाए और स्मृति चिन्ह, पगड़ी आदि भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष तिजेन्द्र दुल, पूर्व मंत्री सुरेंद्र बरवाला, डा. राज सैनी, डा. विजेन्द्र ढांडा, सुनील ढांडा, देवव्रत ढांडा, धूप सिंह, राजेन्द्र सिंह, दिलबाग ढांडा, कुलदीप रंधावा सहित अनेक गण्यमान्य लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम • सीआरएसयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कार्यशाला छात्र साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के साथ साइकोलॉजी भी पढ़ सकेंगे: राज्यपाल

भास्कर न्यूज | जी०

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सीआरएसयू सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। संबोधन में राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि बहुविषयक शिक्षा पर यह विमर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में ठोस प्रयास है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के सपनों को साकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया। आज का विद्यार्थी एक ही विषय तक सीमित नहीं है। अब छात्र साइंस के साथ आर्ट्स या कॉमर्स के साथ साइकोलॉजी जैसे विषय भी पढ़ सकता है। यह लचीलापन शिक्षा को समावेशी और व्यावहारिक बनाता है। पहले आर्ट्स और साइंस के बीच दूरी थी, जिसे यह नीति खत्म करती है। यह केवल शिक्षा सुधार नहीं, सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा ने कृषि, खेल और उच्च शिक्षा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। यहां के लोगों में ऊर्जा है, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में दिशा देनी होगी। विकसित भारत प्रधानमंत्री का सपना है। उसे साकार करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि नीति के तहत विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा दी गई है। इससे शिक्षा लचीली और समावेशी बनेगी।



जी०. कार्यक्रम में मंच पर मौजूद महामहिम राज्यपाल, मंत्री व अन्य अतिथि।



जी०. कार्यशाला में भाग लेते हुए यूनिवर्सिटीज के वीसी व अन्य शिक्षाविद।

शिक्षक की भूमिका केवल पढ़ाने तक ही नहीं रहेगी: डांडा

शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि बहुविषयक शिक्षा से शिक्षक की भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी। वह शोध, रोजगार, अर्थशास्त्र और कौशल विकास में भी योगदान देगा। उन्होंने कहा, नींव डालने से ही इतिहास बनता है। कुलगुरु प्रो. रामपाल सैनी ने कहा, बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं, आत्मबोध, भारतीयता पर गर्व और जीवन मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह नीति विद्यार्थियों को रुचि और क्षमता के अनुसार पढ़ाई का विकल्प देती है।

सीआरएसयू के वाइस चांसलर प्रो. रामपाल सैनी ने मुख्य अतिथि राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा, सीएम के ओएसडी डॉ. राज नेहरू और उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा को स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। कुलसचिव प्रो. लक्लीन मोहन और विवि समिति के अन्य सदस्यों ने सभी वाइस

चांसलरों को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। मौके पर महामहिम राज्यपाल की धर्मपत्नी मित्रा घोष, डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्णलाल मिश्रा, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा के चेयरपर्सन कैलाश चंद्र शर्मा, सीएम के ओएसडी राज नेहरू, सीआरएसयू के वीसी रामपाल सैनी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के वीसी उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों, प्रोफेसरों व अफसरों से किया संवाद नई शिक्षा नीति सिर्फ दस्तावेज नहीं, यह देश के भविष्य का परिवर्तनकारी दृष्टिकोण: राज्यपाल

भास्करन्यूज़ | जी०

हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि नई शिक्षा नीति केवल दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में नए आयाम स्थापित होंगे। हरियाणा ने इसे लागू कर लिया है। उच्च शिक्षा में पहुंच, गुणवत्ता, समानता, स्थिरता व भविष्य की तैयारी मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। जिन पर सरकार का दृष्टिकोण आधारित है।

राज्यपाल सोमवार को जी० की सीआरएस विवि में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार बहु-विषयक शिक्षा... विषय पर कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कहा कि नई नीति में उभरते हुए राष्ट्र की आकांक्षाएं

प्रदेश में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले जल्द होंगे: शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने सेमिनार में नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों, प्रोफेसरों व अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति हर घर के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगी। यह नीति विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा, नई तकनीक और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाएगी। यह बदलाव सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और शिक्षित, सशक्त व आत्मनिर्भर हरियाणा के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही टीचरों के ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि यह लिस्ट हुड्डा, सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ग्रुप की लिस्ट बनकर रह गई।

शामिल हैं। जिसमें युवा बुद्धि के बलबूते पर 21वीं सदी की चुनौतियों व अवसरों के लिए तैयार रहेगा।

इसके आदर्शों को क्रियान्वित करके वर्ष 2047 तक जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, उस समय देश न केवल ज्ञान महाशक्ति होगा, बल्कि शिक्षा का उपयोग करके सच्ची समता, समावेशिता व सतत विकास प्राप्त कर रहा होगा। हम यह सुनिश्चित करें कि बहु-विषयक शिक्षा केवल

नारा न रहे, बल्कि देश की हर कक्षा, प्रयोगशाला और शिक्षण संस्थान में जीवंत वास्तविकता बने। मौके पर सीआरएसयू के वीसी प्रो. रामपाल सैनी ने विवि में नई शिक्षा नीति लागू करने बारे में जानकारी दी। इसमें एक दर्जन से अधिक यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर व प्रतिनिधि पहुंचे और व्याख्यान दिए। वहीं शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, विस डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिश्रा विशेष तौर पर पहुंचे।



राज्यपाल असीम
कुमार घोष



राष्ट्रीय नजर-सबकी खबर

INDIA TIMER

इंडिया टाइमर

में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।

मोबाइल :
9050007221
9467504707

www.indiatimer.com

indiatimer1@gmail.com

indiatimer1

वर्ष : 12

अंक : 2

जिन्दा, 19 अगस्त 2025

पृष्ठ : 4

मूल्य : 3 रुपये

INDIATIMER

@indiatimer1



सियासत ही नहीं शिक्षा के क्षेत्र को भी सशक्त कर रही जींद की धरा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर महामहिम राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं की जींद में हुई कार्यशाला

संजय शर्मा

जींद, (इंडिया टाइमर) : सूबे की सियासत ही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी सशक्त होने के लिए जींद की धरा को चुना जा रहा है। मोदी सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सींचने और उसे पूरी शिद्दत के साथ शिक्षण संस्थानों में सिरि चढ़ाने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने सोमवार को जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए हरियाणा के महामहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में नए आयाम स्थापित होंगे। नई शिक्षा नीति एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेगी। हरियाणा ने इसे लागू कर दिया है और इसके सभी आयामों के लक्ष्य को निश्चित तौर पर हासिल करेगा। उच्च शिक्षा में पहुँच, गुणवत्ता, समानता, स्थिरता और भविष्य की तैयारी वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिन पर राज्य सरकार का दृष्टिकोण आधारित है। कार्यशाला में आयोजित सत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित, बहु-विषयक शिक्षा के विविध पहलुओं पर उच्च गुणवत्तापूर्ण चर्चा हुई। हमारी नई शिक्षा नीति केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो 2025 के अंत तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अधिकांश भाग को लागू करने जा रहा है। यह वास्तव में एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल की धर्मपत्नी मित्रा घोष, शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह डांडा, डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्णलाल मिश्रा, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा के चेयरपर्सन कलाश चन्द्र शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू, सीआरएसयू के वाइस चांसलर रामपाल सैनी सहित प्रदेश के विभिन्न

विश्वविद्यालयों के कुलगुरु उपस्थित रहे। महामहिम राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी के गतिशील नेतृत्व में प्रगति और विकास का पर्याय बन रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक उभरते हुए राष्ट्र की आकांक्षाएँ शामिल हैं, जिसमें युवा अपनी बुद्धि के बलवृत्त पर 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार रहेगा। तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में, जहाँ विज्ञान और मानविकी, प्रौद्योगिकी और कला, अनुसंधान और उद्यमिता के बीच की सीमाएँ लगातार कमजोर होती जा रही हैं, यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली समग्र विचारकों, नवप्रवर्तकों और समस्या-समाधान कर्ताओं का पोषण करेगी। विषयों का यह सम्मिश्रण रचनात्मकता को प्रेरित करेगा। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और हमारे छात्रों को अनिश्चित दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक अनुकूलन शीलता विकसित करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की सोच के अनुरूप 2047 तक विकसित भारत का विजन, एक समृद्ध, समावेशी, विश्व स्तर पर सम्मानित भारत, इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज जन्मानुस का कितने प्रभावी ढंग से पोषण करते हैं, शिक्षा ही इस यात्रा की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में लचीला पाठ्यक्रम छात्रों को अपनी गति और तरीके से सोखने की अनुमति देता है। इस



शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में होंगे नए आयाम स्थापित : असीम कुमार घोष

महत्वाकांक्षी एजेंडे की सफलता केवल नीतिगत घोषणाओं पर ही नहीं, बल्कि उसे साकार करने के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता शिक्षकों, प्रशासकों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और समाज पर निर्भर करेगी। हमें शिक्षक प्रशिक्षण, विकास प्राप्त कर रहा होगा। उन्होंने आह्वान किया

शिक्षा मंत्री ने शिक्षाविदों से विचार किये सांझे

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि सरकार द्वारा मॉडल स्कूल, स्कूल हब और बहु-प्रवेश, निष्कास प्रणाली को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों को लचीला और आधुनिक शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। शिक्षा मंत्री ने सेमिनार में नई शिक्षा नीति पर 1-दिवसीय वर्कशॉप में शामिल होकर शिक्षाविदों, प्रोफेसरों व अधिकारियों से संवाद किया और अपने विचार साझा किए। शिक्षा मंत्री के रूप में मेरा दृढ़ विश्वास है कि नई शिक्षा नीति हर घर के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगी। यह नीति विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा, नई तकनीक और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाएगी। यह बदलाव सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और शिक्षित, सशक्त व आत्मनिर्भर हरियाणा के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने वर्कशॉप में शामिल अपने अनुभव और विचार साझा कर इस नीति को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग दिया।

डिजिटल बुनियादी ढाँचे, अनुसंधान तंत्र के साथ-साथ अपने शिक्षार्थियों में नैतिकता, सहानुभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों को स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आदर्शों को क्रियान्वित करके वर्ष 2047 तक

कि हम स्वयं को इस महान मिशन के लिए समर्पित करें और यह सुनिश्चित करें कि बहु-विषयक शिक्षा केवल एक नारा न रहे, बल्कि देश भर की प्रत्येक कक्षा, प्रयोगशाला और शिक्षण संस्थान में एक जीवंत वास्तविकता बने।

शिक्षा क्षेत्र के प्रदेश में होंगे नए आयाम स्थापित : असीम घोष



महमहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष को स्मृति चिह्न भेंट करते हुए डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिश्रा और शिक्षा मंत्री महिपाल दांडा और उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरु।



शिक्षाविदों से विचार किये सांझे

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल दांडा ने कहा कि सरकार द्वारा मॉडल स्कूल, स्कूल हब और बहु-प्रवेशनिकास प्रणाली को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों को लचीला और आधुनिक शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। शिक्षा मंत्री ने सेमिनार में नई शिक्षा नीति पर 1-दिवसीय वर्कशॉप में शामिल होकर शिक्षाविदों, प्रोफेसर्स व अधिकारियों से संवाद किया और अपने विचार सांझा किए। शिक्षा मंत्री के रूप में मेरा दृढ़ विश्वास है कि नई शिक्षा नीति हर घर के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगी। यह नीति विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा, नई तकनीक और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाएगी। यह बदलाव सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और शिक्षित, सशक्त व आत्मनिर्भर हरियाणा के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने वर्कशॉप में शामिल अपने अनुभव और विचार सांझा कर इस नीति को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग दिया।

जींद, संजय शर्मा (पंजाब केसरी) : सूत्रों की सियासत ही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी सशक्त होने के लिए जींद की धरा को चुना जा रहा है। मोदी सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सँचने और उसे पूरी शिद्दत के साथ शिक्षण संस्थानों में सिर चढ़ाने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने सोमवार को जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए हरियाणा के महामहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में नए आयाम स्थापित होंगे। नई शिक्षा नीति एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेगी। हरियाणा ने इसे लागू कर दिया है और इसके सभी आयामों के लक्ष्य को निश्चित तौर पर हासिल करेगा। उच्च शिक्षा में पहुँच, गुणवत्ता, समानता, स्थिरता और भविष्य की तैयारी वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिन पर राज्य सरकार का दृष्टिकोण आधारित है। कार्यशाला में आयोजित सत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित, बहु-विषयक शिक्षा के विविध पहलुओं पर उच्च गुणवत्तापूर्ण चर्चा हुई। हमारी नई शिक्षा नीति केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो 2025 के अंत तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अधिकांश भाग को लागू करने जा रहा है। यह वास्तव में एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल की धर्मपत्नी मित्रा घोष, शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह दांडा, डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्णलाल मिश्रा, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा के चेयरमैन कैलाश

सियासत ही नहीं शिक्षा के क्षेत्र को भी सशक्त कर रही जींद की धरा

चन्द्र शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू, सीआरएसयू के वाइस चांसलर रामपाल सेन सहित प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरु उपस्थित रहे। महामहिम राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सेन के गतिशील नेतृत्व में प्रगति और विकास का पर्याय बन रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक उभरते हुए राष्ट्र की आकांक्षाएँ

शामिल हैं, जिसमें युवा अपनी बुद्धि के बलबूते पर 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार रहेगा। तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में, जहाँ विज्ञान और मानविकी, प्रौद्योगिकी और कला, अनुसंधान और उद्यमिता के बीच की सीमाएँ लगातार कमजोर होती जा रही हैं, यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली समग्र विचारकों, नवप्रवर्तकों और समस्या-समाधान कर्ताओं का पोषण करेगी। विषयों का यह सम्मिश्रण रचनात्मकता को प्रेरित करेगा।

आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और हमारे छात्रों को अनिश्चित दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक अनुकूलन शीलता विकसित करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप 2047 तक विकसित भारत का विजन, एक समृद्ध, समावेशी, विश्व स्तर पर सम्मानित भारत, इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज जनमानस का कितने प्रभावी ढंग से पोषण करते हैं, शिक्षा ही इस यात्रा की आधारशिला है।

पंजाब केसरी

Tue, 19 August 2025

<https://mpaper.punjabkesari.com/c/77979696>



नई शिक्षा नीति दस्तावेज नहीं, भविष्य के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण : राज्यपाल



जींद में राज्यपाल असीम कुमार घोष को पौधा भेंट करते शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिह्रा। • सौ. विवि

जागरण संवाददाता • जींद : चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में सोमवार को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार बहु-विषयक शिक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि राज्यपाल असीम कुमार घोष पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में नए आयाम स्थापित होंगे।

नई शिक्षा नीति एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेगी। उच्च शिक्षा में पहुंच, गुणवत्ता, समानता, स्थिरता और भविष्य की तैयारी वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिन पर राज्य सरकार का दृष्टिकोण आधारित है। सेमिनार में आयोजित सत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित, बहु-विषयक शिक्षा के विविध पहलुओं पर उच्च गुणवत्तापूर्ण चर्चा हुई। हमारी नई

हर बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की रखी जाएगी नींव

सुबह कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सरकार द्वारा माडल स्कूल, स्किल हब और बहु-प्रवेश को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति हर घर के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगी। यह नीति विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा, नई तकनीक और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाएगी।

शिक्षा नीति केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो 2025 के अंत तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अधिकांश भाग को लागू करने जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में होंगे नए आयाम स्थापित

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने में हरियाणा देश का पहला राज्य: महामहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष

सवेरा न्यूज़/नरेंद्र

जौद, 18 अगस्त : हरियाणा के महामहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में नए आयाम स्थापित होंगे। नई शिक्षा नीति एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेगी। हरियाणा ने इसे लागू कर लिया है और इसके सभी आयामों के लक्ष्य को निश्चित तौर पर हासिल करेगा। उच्च शिक्षा में पहुँच, गुणवत्ता, समानता, स्थिरता और भविष्य की तैयारी वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिन पर राज्य सरकार का दृष्टिकोण आधारित है। सेमिनार में आयोजित सत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित, बहु-विषयक शिक्षा के विविध पहलुओं पर उच्च गुणवत्तापूर्ण चर्चा हुई। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो 2025 के अंत तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अधिकांश भाग को लागू करने जा रहा है। यह वास्तव में एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद को बधाई दी। महामहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में



राज्यपाल को स्मृति विह्वल भेंट करते डिप्टी स्पीकर व शिक्षा मंत्री व कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोग व विद्यार्थी।

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार बहु-विषयक शिक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में प्रगति और विकास का पर्याय बन रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक उभरते हुए राष्ट्र की आकांक्षाएँ शामिल हैं, जिसमें युवा अपनी बुद्धि के बलबूते पर 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार रहेगा। तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में, जहाँ विज्ञान और मानविकी, प्रौद्योगिकी और कला, अनुसंधान और उद्यमिता के बीच की सीमाएँ लगातार कमजोर होती जा रही हैं। विषयों का यह सम्मिश्रण रचनात्मकता को प्रेरित करेगा। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और हमारे छात्रों को अनिश्चित दुनिया में सफल

होने के लिए आवश्यक अनुकूलन शीलता विकसित करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप 2047 तक विकसित भारत का विजन, एक समृद्ध, समावेशी, विश्व स्तर पर सम्मानित भारत, इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज जनमानस का कितने प्रभावी ढंग से पोषण करते हैं, शिक्षा ही इस यात्रा की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में लचीला पाठ्यक्रम छात्रों को अपनी गति और तरीके से सीखने की अनुमति देता है। इस महत्वाकांक्षी एजेंडे की सफलता केवल नीतिगत घोषणाओं पर ही नहीं, बल्कि उसे साकार करने के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता शिक्षकों, प्रशासकों, नीति निमाताओं, उद्योग जगत और समाज पर निर्भर करेगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सरकार द्वारा मॉडल स्कूल, स्किल हब और बहु-प्रवेश/निकास प्रणाली को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों को

लचीला और आधुनिक शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। शिक्षा मंत्री ने सेमिनार में नई शिक्षा नीति पर 1-दिवसीय वर्कशॉप में शामिल होकर शिक्षाविदों, प्रोफेसरों व अधिकारियों से संवाद किया और अपने विचार साझा किए।

शिक्षा मंत्री के रूप में मेरा दृढ़ विश्वास है कि नई शिक्षा नीति हर घर के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने वर्कशॉप में शामिल अपने अनुभव और विचार साझा कर इस नीति को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग दिया।

इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल की धर्मपत्नी मित्रा घोष, डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्णलाल मिह्रा, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा के चेयरपर्सन कैलाश चन्द्र शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू, सीआरएसयू के कुलगुरु रामपाल सैनी, कुलसचिव प्रो. लवलीन मोहन सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरु उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में होंगे नए आयाम स्थापित

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने में हरियाणा देश का पहला राज्य: राज्यपाल असीम कुमार घोष

राज्यपाल ने सीआरएसयू में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहु दिवसीय कार्यशाला में की शिरकत।

हरिभूमि न्यूज

हरियाणा के महामहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में नए आयाम स्थापित होंगे। नई शिक्षा नीति एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेगी। हरियाणा ने इसे लागू कर लिया है और इसके सभी आयामों के लक्ष्य को निश्चित तौर पर हासिल करेगा। उच्च शिक्षा में पहुंच, गुणवत्ता, समानता, स्थिरता और भविष्य की तैयारी वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। जिन पर राज्य सरकार का दृष्टिकोण आधारित है। सेमिनार में आयोजित सत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित, बहुविषयक शिक्षा के विविध पहलुओं पर उच्च गुणवत्तापूर्ण चर्चा हुई। हमारी नई शिक्षा नीति केवल एक दस्तावेज



जींद। महामहिम राज्यपाल को पौधा भेंट करते हुए शिक्षा मंत्री व डिप्टी स्पीकर।



जींद। कार्यशाला को संबोधित करते महामहिम राज्यपाल असीम घोष।



जींद। महामहिम राज्यपाल की पत्नी को स्मृति चिह्न देते हुए।

नई शिक्षा नीति हर घर के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगी: बांडा

शिक्षा मंत्री नरिंदर सिंह बांडा ने कहा कि सरकार द्वारा मॉडल स्कूल, स्किल हब और बहुप्रवेशनिका प्रणाली को प्रथमिकता दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों को लचीला और आधुनिक शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। शिक्षा मंत्री ने सेमिनार में नई शिक्षा नीति पर एक दिवसीय वर्कशॉप में शामिल होकर शिक्षाविदों, प्रोफेसरों व अधिकारियों से संवाद किया और अपने विचार साझा किए। शिक्षा मंत्री के रूप में मेरा दृढ़ विश्वास है कि नई शिक्षा नीति हर घर के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगी। यह नीति विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा, नई तकनीक और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाएगी। यह बदलाव सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अनेक बाली पोटियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए और शिक्षित, सशक्त व आत्मनिर्भर हरियाणा के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति केजपस में वार्षिक रूप से पढ़ते और वर्तमान पौढ़ों में समाहित हो। भारत के शिक्षा के क्षेत्र में यह एक कारिकारी परिवर्तन है।

नहीं है बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो 2025 के अंत तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधिकांश

भाग को लागू करने जा रहा है। यह वास्तव में एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। महामहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष सोमवार को चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में

यह लोग रहे मौजूद

इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल की धर्मपत्नी मित्रा घोष, डिप्टी स्पीकर डा. कृष्णलाल मिह्ला, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा के चैंपियन कैलाश चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू, सीआरएसयू के कुलसचिव राजपाल सैनी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलसचिव उपस्थित रहे।

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुविषयक शिक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नावय सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में प्रगति और विकास का पर्याय बन रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक उभरते हुए राष्ट्र की आकांक्षाएं शामिल हैं। जिसमें युवा अपनी बुद्धि के बलबूते पर 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार रहेगा। तेजी

से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में, जहां विज्ञान और मानविकी, प्रौद्योगिकी और कला, अनुसंधान और उद्यमिता के बीच की सीमाएं लगातार कमजोर होती जा रही हैं, यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली समग्र विचारकों, नवप्रवर्तकों और समस्या समाधान कर्ताओं का पोषण करेगी। विषयों का यह समिश्रण रचनात्मकता को प्रेरित करेगा। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और हमारे छात्रों को अनिश्चित दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक अनुकूलन शीलता विकसित करने में सक्षम बनाएगा।

महान मिशन के लिए समर्पित रहें

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आदर्शों को क्रियान्वित करके वर्ष 2047 तक जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, उस समय भारत न केवल एक ज्ञान महाशक्ति होगा बल्कि एक ऐसा राष्ट्र भी होगा जो शिक्षा का उपयोग करके सच्ची समता, समावेशिता और सतत विकास प्राप्त कर रहा होगा। उन्होंने आह्वान किया कि हम स्वयं को इस महान मिशन के लिए समर्पित करें और यह सुनिश्चित करें कि बहुविषयक शिक्षा केवल एक मारा न रहे बल्कि देश भर की प्रत्येक कक्षाएं प्रयोगशाला और शिक्षण संस्थान में एक जीवंत कार्यावृत्ति बनें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप 2047 तक विकसित भारत का चिजन, एक समृद्ध, समावेशी, विश्व स्तर पर सम्मानित भारत इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज जनमानस को कितने प्रभावी ढंग से पोषण करते हैं। शिक्षा ही इस यात्रा की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में लक्ष्य पठ्यक्रम छात्रों को अपनी गति और तरीके से सीखने की अनुमति देता है। इस मूल्यकांक्षी धर्जे की सफलता केवल निरंतर घोषणाओं पर ही नहीं बल्कि उसे साकार करने के लिए हमारी समुचित प्रतिबद्धता शिक्षकों, प्रशासकों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और समाज पर निर्भर करेगी। हमें शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल बुनियादी ढांचे, अनुसंधान तंत्र के साथ-साथ अपने शिक्षार्थियों में नैतिकता, सहस्रभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों को स्थापित करना चाहिए।